(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को निरन्तर हो रहे भारी घाटे के कारणों का गम्भीरता से पता लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन कारणों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बी. रंगैया नायडू) : (क) से (ङ) इस सरकार द्वारा 1989 में डेसू द्वारा बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र (बी.टी.पी.स.) को देय 1109.73 करोड रु० की राशि तथा 31.3.1989 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय ऋणों पर लगने वाले ब्याज की 297.42 करोड़ रुपये की राशि को, डेसू की वित्तीय वसूली योजना के एक अंग के रूप में बट्टे खाते में डाला गया था। घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली की दरों में मार्च, 1991 में विभिन्न स्लैबों के लिए 48% से बढ़ाकर 166% कर दिया गया था। लघु औद्योगिक श्रेणी में यह वृद्धि 67% थी तथा बृहत औद्योगिक श्रेणी के सन्दर्भ में यह वृद्धि 50% थी तथा ऊर्जा प्रभार 44% थे। 1993–94 में डेसू को कैश फ्लो आधार पर लगभग 473 करोड़ रुपये का घाटा होने की संभावना है। 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार डेसू बी.टी.पी.एस. को 2546 करोड़ रुपये का देनदार है। उत्पादित विद्युत तथा खरीदी गई विद्युत दोनों की लागतों में वृद्धि होने, अधिक खर्च, अधिक पारेषण एवं वितरण हानियों तथा कुछ श्रेणियों के लिए अप्रयुक्त टैरिफ इत्यादि के कारण डेसू राजस्व की कमी का सामना कर रहा है। डेसू की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार समय-समय पर डेसू के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करती है।

बदरपुर विद्युत केन्द्र में उत्पादन में कमी आना

1689. **श्री राम जेठमलानी :**
डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में पिछले कई महीनों के दौरान हो रहे औसत विद्युत उत्पादन की तुलना में अप्रैल, 1993 से विद्युत उत्पादन कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले महीनों में विद्युत उत्पादन की औसत मात्रा कितनी थी तथा 1 अप्रैल, 1993 को कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन किया गया;

(ग) बदरपुर विद्युत केन्द्र में अपर्याप्त मात्रा में विद्युत का उत्पादन होने के कौन-कौन से कारण हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा विद्युत के उत्पादन में आई इस गिरावट पर रोक लगाने के लिए कोई प्रतिरोधात्मक उपाय किए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बी. रंगैया नायडू) : (क) से (ङ) बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से अप्रैल, 1993 से 374 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया जबकि अप्रैल, 1992 में यह उत्पादन 354 मिलियन यूनिट था तथा 1992–93 में मासिक औसत विद्युत उत्पादन 381 मिलियन यूनिट था। अतः बदरपुर की विद्युत उत्पादन करने की स्थिति संतोषजनक है। पर्याप्त विद्युत उत्पादन किए जाने के लिए सरकार बदरपुर को कोयले की निर्बाध रूप से सप्लाई किया जाना सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है।

Cummulative losses of the SEBs

1690. SHRI SURESH PACHOURI:
SHRI IQBAL SINGH:

Will the Minister of **POWER** be pleased to state:

(a) what are the cumulative losses of the State Electricity Boards (State-wise);

(b) what are the reasons for the

dismal performance of State Electricity Boards; and

(c) what steps are taken by Government to improve the functioning of the SEBs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) A Statement showing the cumulative surplus/deficit of the State Electricity Boards as on 31.3.1993 is enclosed. (*See* below)

(b) The major reasons for the unsatisfactory financial performance of the State Electricity Boards include un-realistic power tariff structure including for the agricultural tariff, non-payment of RE subsidy to SEBs by the State Governments, non-conversion of loan into equity, low level of PLF, high T&D losses, high fuel consumption in the thermal power stations etc.

(c) State Governments have been advised to undertake measures such as equity participation, rationalised tariff, regular payment of Rural Electrification subsidy, improvement in Plant Load Factor, reduction in T&D losses etc. to improve the finances of State Electricity Boards. Recently, the Conference of Power Ministers held on 8th and 9th January, 1993 also discussed about the ways and means to improve the performance of SEBs both in physical and financial terms and has adopted an Action Plan containing steps to improve the performance of SEBs during the 8th Five Year Plan. These include payment of RE subsidy to the SEBs in time, as also liquidation of the arrears of subsidy in a phased manner, reduction in outstanding dues, tariff rationalisation, improvement in PLF and reduction in T&D losses etc.

Statement

Cumulative Surplus/(Deficit) in respect of SEBs as on 31-3-93.

(Rs. in crores)

Sl. No.	Name of SEBs	Cumulative Surplus/ Deficit as on 31-3-9
1.	Andhra Pradesh (A)	427.70
2.	Bihar (U)	—1238.04
3.	Gujarat (U)	—425.65
4.	Haryana (U)	—1225.21
5.	Himachal Pradesh (U)	—101.83
6.	Karnataka (A)	—366.57
7.	Kerala (U)	—134.90
8.	Madhya Pradesh (P)	461.99
9.	Maharashtra (A)	638.16
10.	Orissa (U)	—411.33
11.	Punjab (U)	—505.29
12.	Rajasthan (P)	—776.83
13.	Tamil Nadu (U)	305.74
14.	Uttar Pradesh (P)	—39.389
15.	West Bengal (U)	—514.0
16.	Assam (P)	—1131.25
17.	Meghalaya (P)	—16.95
	TOTAL : SEBs	—4683.73